गौमाता राष्ट्रमाता
स्वतःस्फूर्त गौ-प्रतिष्ठा आन्दोलन

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान
RNI No. : MAHHIN/2008/24084. www.rashtriyaswabhimaan.com

वर्ष : 17 | अंक : 56 | मुंबई, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 | पृष्ठ : 4 | मूल्य 1 रुपए

खबर संक्षेप

बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ 12 यात्री घायल

बर्धमान। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम यात्रियों की भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 10-12 लोग घायल हुए। घायलों में से 6 को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब प्लेटफॉर्म 4, 6 और 7 पर लगभग एक ही समय में तीन ट्रेनें खड़ी थीं। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में यात्री प्लेटफॉर्म 4 और 6 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज की ओर दौड़े। संकरी सीढ़ियों पर अचानक भीड़ बढ़ने से अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कई यात्री गिर गए और भीड़ में दबकर घायल हो गए।

सूचना मिलते ही रेलवे की राहत और बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और भीड़ प्रबंधन में हुई कमियों की पहचान की जाएगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि भीड़ वाली जगहों पर सतर्क रहें और स्टेशन पर अनुशासन बनाए रखें ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों।

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराकर वनडे इतिहास का सबसे बड़ा चेज किया

विशाखापत्तनम। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-13 में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हराया। यह मुकाबला विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना और प्रतीका की शानदार फिफ्टी के दम पर 331 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। लेकिन इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसे केवल 49 ओवर में ही हासिल कर लिया और वनडे महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चेज दर्ज किया।

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत जोरदार अंदाज में की थी। उसने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका और अब ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। मंधाना और प्रतीका के शतकीय प्रदर्शन के बावजूद भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए और बड़ी जीत का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके।

दूसरी ओर, वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने पहले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को पराजित किया था, जबकि श्रीलंका के खिलाफ उनका मैच धुल गया था। ऑस्ट्रेलिया की यह जीत उन्हें टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर बनाए रखने में मदद करेगी और साथ ही भारत के लिए आगामी मैचों में चुनौती बढ़ा दी है।

विशाखापत्तनम के इस मुकाबले ने दर्शकों को रोमांचक अंत तक बांधे रखा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेले और दबाव में भी कूल प्रदर्शन किया, जिससे यह चेज वनडे इतिहास में सबसे यादगार और सबसे बड़ी चेज के रूप में दर्ज हो गया। भारतीय टीम अब अपनी रणनीति सुधारकर आगे के मैचों में वापसी करने की कोशिश करेगी।

दुर्गापुर में गैंगरेप के बाद ममता सरकार पर विवाद, महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल

बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। इस भयावह वारदात ने राज्य की कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यह टिप्पणी कि "लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए" ने विवाद और बढ़ा दिया। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने इसे "संवेदनहीन और शर्मनाक" बताते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में इस तरह की गंभीर घटना सामने आई हो। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था, जिससे राज्यभर में आक्रोश फैला था। डॉक्टरों की हड़ताल और कोर्ट द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल अब भी बरकरार हैं। इससे पहले कसबा लॉ कॉलेज और अन्य जगहों पर भी रेप की घटनाओं ने राज्य में चिंता बढ़ाई थी। शुक्रवार रात ओडिशा की रहने वाली दूसरी वर्ष की छात्रा अपनी सहेली के साथ कॉलेज कैंपस के बाहर खाने गई थी। इसी दौरान तीन अज्ञात युवकों ने उसका फोन छीनकर उसे पास के जंगल में ले जाकर बलात्कार किया। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और बाद में मोबाइल लौटाने के लिए पैसे की मांग भी की।

बिहार में भाजपा और जदयू के बीच बराबर सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फार्मूला हुआ तय

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला अंतिम रूप दे दिया है। इस तय फॉर्मूले के अनुसार जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ही 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सहयोगी दलों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को छह-छह सीटें दी गई हैं। इस समझौते के बाद गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई "बड़ा भाई" नहीं है और दोनों प्रमुख दल बराबर के साझेदार हैं।

सीट बंटवारे में सबसे बड़ा लाभ चिराग पासवान को मिला। भाजपा शुरू में उन्हें केवल 22 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी मांग पर कायम रहते हुए 29 सीटें हासिल कीं। इसके अलावा, उन्होंने अपनी पसंद की तीन प्रमुख सीटें — हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर — भी अपने खाते में रख ली हैं। हालांकि, पिछली बार 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद लोजपा (रामविलास) केवल एक सीट जीत पाई थी, इसलिए इस बार चिराग के सामने अपनी "स्ट्राइक रेट" साबित करने की चुनौती होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को छह-छह सीटें देकर भाजपा-जदयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि गठबंधन में कोई दल उपेक्षित नहीं रहेगा। सूत्रों के अनुसार, उपेंद्र कुशवाहा को उजियारपुर, महुआ, दिनारा, सासाराम, बाजपट्टी और मधुबनी जैसी सीटें मिल सकती हैं। मांझी शुरू में असंतोष में थे और उन्होंने 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद वे सहमत हो गए और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, "हम आखिरी सांस तक पीएम मोदी के साथ हैं।"

इस बार जदयू और भाजपा दोनों ने सीटों में कटौती की है — जदयू 115 से घटकर 101 और भाजपा 110 से घटकर 101 पर आ गई है। यह कदम गठबंधन में शक्ति संतुलन बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है।

वहीं, विपक्षी महागठबंधन राजद-कांग्रेस ने अभी तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं की है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, NDA का यह फॉर्मूला नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की संयुक्त रणनीति का हिस्सा है, जो बिहार में सत्ता बनाए रखने और चुनावी बढ़त हासिल करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

दलित IPS पूरन कुमार के परिवार के लिए न्याय की लड़ाई: पंजाब में AAP का जन आंदोलन

चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) ने दलित आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के परिवार के न्याय की मांग को लेकर व्यापक जन समर्थन जुटाया है। पूरन कुमार की हालिया मौत और हरियाणा की भाजपा सरकार की निष्क्रियता ने राज्य में सामाजिक चेतना को झकझोर दिया है। AAP ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक अफसर की मौत का मामला नहीं है, बल्कि यह न्याय, समानता और सामाजिक सम्मान की लड़ाई है।

पूरन कुमार, जो दलित समाज से आने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे, ने हाल ही में आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने न्याय की लगातार मांग की, लेकिन पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में हुई देरी से यह स्पष्ट हुआ कि सत्ता तंत्र ने उनके मामले को दबाने की कोशिश की। इसी विरोध और असंतोष को लेकर AAP ने यह मुद्दा जन आंदोलन में बदल दिया है। पंजाब की सड़कों पर अब इंसाफ की आवाज गूंज रही है।

प्रदेश के प्रमुख जिलों में कैंडल मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। अमृतसर में हरभजन सिंह ETO, जालंधर में मोहिंदर भगत, पटियाला में MLA गुरदेव देवमान और चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेता इन मार्चों का नेतृत्व करेंगे। AAP ने कहा कि यह केवल प्रतीकात्मक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि संदेश है कि जब सत्ता अन्याय पर चुप रहती है, तो जनता सक्रिय होकर जवाब देती है।

इस आंदोलन को डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जोड़ा गया है। बाबा साहेब के न्याय, समानता और गरिमा के सिद्धांतों की रक्षा के लिए यह मोर्चा खोला गया है। पूरन कुमार जैसे ईमानदार अफसरों के साथ हुए अन्याय को पंजाब की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज की गरिमा के लिए है।

AAP ने कहा कि भाजपा सरकार की संवेदनहीनता यह दर्शाती है कि दलित समाज के दर्द को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लेकिन इतिहास यह भी दिखाता है कि जब सत्ता आवाज दबाने की कोशिश करती है, तो सड़क पर जनसमर्थन निर्णायक साबित होता है। पूरे पंजाब में मोमबत्तियां जलाकर एक स्वर में इंसाफ की मांग उठाई जा रही है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन पूरन कुमार को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।

ट्रंप मध्य पूर्व शांति मिशन पर, मिस्र में 20 देशों के साथ सीजफायर पर चर्चा

वाशिंगटन/यरुशलेम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को इजराइल और मिस्र के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य इजराइल-हमास युद्ध में सीजफायर (युद्धविराम) और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने को अंतिम रूप देना है। सूत्रों के अनुसार, समझौते के तहत 48 बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू हो सकती है।

ट्रंप सबसे पहले इजराइल जाएंगे, जहां वे कनेसेट (इजराइल की संसद) को संबोधित करेंगे। यह गौरतलब है कि आखिरी बार 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने कनेसेट में भाषण दिया था। इसके बाद ट्रंप मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी के साथ शर्म-अल-शेख में अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन की सह-मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता भाग लेंगे और गाजा समेत पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति और स्थिरता के संभावित रोडमैप पर चर्चा करेंगे। समझौते के पहले चरण में हमास 48 बंधकों को छोड़ेगा, जिनमें लगभग 20 अभी जीवित हैं। इसके बदले में इजराइल 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस दौरान गाजा में मानवीय सहायता, जैसे खाद्य सामग्री और दवाओं की आपूर्ति शुरू की जाएगी। इजराइली सेना कुछ प्रमुख शहरों से आंशिक रूप से पीछे हट रही है।

युवा शक्ति का महासंग्राम: जब क्लासरूम से निकली 'विकसित भारत' की चिंगारी

नई दिल्ली। रविवार की सुबह नई दिल्ली का वातावरण कुछ अलग था। देशभर के लाखों छात्रों के दिलों में उत्साह और सपनों की लहर दौड़ रही थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को संबोधित करते हुए एक ऐसा आह्वान किया, जिसने हर छात्र के भीतर देश के निर्माण की भावना को फिर से जगा दिया। उन्होंने कहा — "युवा शक्ति ही विकसित भारत की धड़कन है।" यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं था, यह एक पुकार थी — देश के भविष्य को अपने हाथों से गढ़ने की।

यह पुकार थी 'विकसित भारत बिल्डथॉन 2025' की — एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन, जहाँ विचारों से निर्माण की यात्रा शुरू होती है। प्रधान ने कहा कि अब क्लासरूम केवल पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि प्रयोगशालाएँ बन रही हैं, जहाँ आइडिया इनोवेशन में बदल रहे हैं और इनोवेशन राष्ट्र निर्माण की दिशा तय कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को बताया कि 13 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारत के लाखों युवा दिमाग एक साथ जुड़ेंगे — न किसी परीक्षा के लिए, न किसी डिग्री के लिए, बल्कि एक विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए। यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक महाअभियान है — रचनात्मकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास का उत्सव।

शिक्षा मंत्री ने छात्रों से कहा, "तुम्हारा एक विचार किसी गाँव का चेहरा बदल सकता है, किसी स्कूल को नई रोशनी दे सकता है या किसी पूरे समुदाय को नई दिशा दिखा सकता है। यही विचार 'विकसित भारत बिल्डथॉन' का सार है।" प्रधान ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने विचारों को सीमाओं से परे ले जाएँ। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत — इन चार मुख्य थीम्स पर काम करते हुए वे ऐसा समाधान खोजें जो देश को तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा, "यह बिल्डथॉन वही मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के सपने को वास्तविकता में बदला जा सकता है।" छात्रों की आँखों में चमक थी, मन में उमंग थी। किसी के मन में ग्रामीण शिक्षा को डिजिटल बनाने का विचार था, तो कोई सोच रहा था कि किस तरह स्थानीय संसाधनों से पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा पैदा की जाए। कई टीमें पहले से तैयारी में जुट चुकी थीं — कुछ स्कूलों ने अपने आइडिया क्लासरूम स्तर पर परखा, तो कुछ ने छोटे मॉडल तैयार किए। बच्चे अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले रहे थे, और हर स्कूल में नवाचार की एक हवा चल पड़ी थी। प्रधान ने कहा, "आपका आइडिया केवल एक सोच नहीं है, यह भारत की दिशा तय करने वाली शक्ति है। vbb.mic.gov.in पर रजिस्टर करें, और अपनी कल्पना को उड़ान दें। भर लो उड़ान, छू लो आसमान।" उनकी यह पंक्ति छात्रों के दिलों में गूँज उठी। 'विकसित भारत बिल्डथॉन 2025' का उद्देश्य केवल प्रतिभा प्रदर्शन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की चेतना को जगाना है। इसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE के सहयोग से शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि देश के स्कूलों में पढ़ने वाला हर छात्र भविष्य का इनोवेटर है, और यदि उसकी सोच को दिशा दी जाए, तो भारत दुनिया का इनोवेशन हब बन सकता है।

संविधान और न्यायपालिका ने भारत को उसके पड़ोसी देशों से अलग और विशिष्ट बनाया है : सीजेआईगवई

रत्नागिरी के मंदनगढ़ तालुका में रविवार का दिन विशेष रहा। यहाँ नए न्यायालय भवन का उद्घाटन करने आए भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए संविधान, न्यायपालिका और राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान ने भारत को न केवल एक मजबूत राष्ट्र बनाया है, बल्कि पड़ोसी देशों में जारी अशांति और उथल-पुथल से इसे अलग खड़ा रखा है। सीजेआई गवई ने अपने भाषण में कहा कि भारत ने विभिन्न युद्धों और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद एकजुटता बनाए रखी। उन्होंने याद दिलाया कि देश ने आंतरिक आपातकाल जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन संविधान की बदौलत लोकतंत्र और न्यायपालिका मजबूत बने रहे। उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को इस स्थिरता का मुख्य स्तंभ बताया। गवई ने श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल में हुई नागरिक अशांति का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां सरकारों में बदलाव, दंगे और आगजनी ने आम नागरिकों को गहरी परेशानियों में डाल दिया। इसके विपरीत भारत में संविधान ने नागरिकों को सुरक्षा, न्याय और अधिकार प्रदान किए।

न्यायिक बुनियादी ढांचे और विकेंद्रीकरण पर भी मुख्य न्यायाधीश ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 22 वर्षों में न्यायपालिका में न्याय के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया गया। विशेष रूप से कोल्हापुर सर्किट बेंच और मंदनगढ़ न्यायालय भवन का निर्माण दो वर्षों में पूरा करना उनके लिए अत्यंत संतोषजनक अनुभव रहा। उन्होंने न्यायपालिका के इस प्रयास को अंतिम नागरिक तक न्याय पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

सीजेआई ने यह भी कहा कि नए भवन का बाबासाहेब अंबेडकर के पैतृक गांव अंबावडे के पास स्थित होना एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है। यह न्यायालय न केवल आधुनिक न्यायिक सुविधाएँ प्रदान करेगा, बल्कि अंबेडकर के सपनों को साकार करने का माध्यम भी बनेगा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि ये न्यायालय न्याय की गति को और तेज करेंगी।

अपने भाषण में गवई ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से ही न्याय की उम्मीद कायम रहती है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से वित्तीय सहयोग प्राप्त होना चाहिए ताकि सभी नागरिकों तक शीघ्र और निष्पक्ष न्याय पहुँच सके। उन्होंने हाल ही में नासिक, नागपुर, कोल्हापुर और दरियापुर में नए न्यायालय भवनों के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का यह संदेश स्पष्ट था: संविधान भारत को मजबूत और एकजुट बनाता है, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, और कार्यपालिका के सहयोग से ही न्याय का वास्तविक लाभ जनता तक पहुँच सकता है। रत्नागिरी में नए भवन का उद्घाटन न केवल एक भौतिक संरचना का आयोजन था, बल्कि यह लोकतंत्र, न्याय और संविधान की स्थिरता का प्रतीक भी बना।

राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने पर अडाणी-अंबानी समूह की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा : हर्षवर्धनसपकाल

मुंबईः महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में लोकतंत्र, गरीबों, मजदूरों और भूमिपुत्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ विश्वास जताया कि 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने पर अदानी और अंबानी की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा।कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में आयोजित 'घर हक परिषद' में हर्षवर्धन सपकाळ की अध्यक्षता में पूर्व सांसद, कांग्रेस पदाधिकारी और समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे महानगर में घर खरीदना आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है, इसलिए किफायती आवास उपलब्ध कराना कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने आवास के अधिकार के लिए अपनी भूमिका तय करें, और कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी।इसके साथ ही, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के शिक्षक विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार समारोह भी संपन्न हुआ। राज्यभर से आए आदर्श शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक विधायक जयंत आसगांवकर, विधायक साजिद खान पठान, शिक्षक विभाग के अध्यक्ष पू. प्रकाश सोनावणे और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

सीमा पर आग और सन्नाटा: जब स्पिन बोलदाक-चमन की रेखा बनी युद्धभूमि

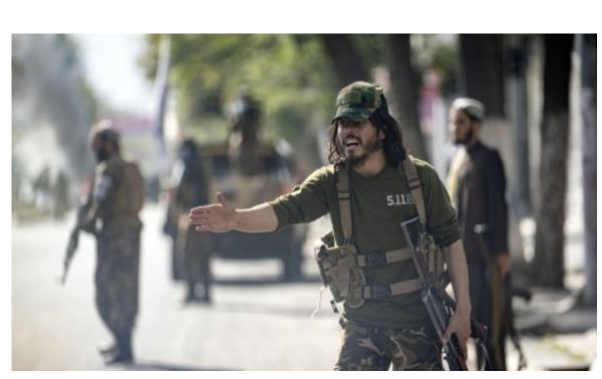

इस्लामाबाद। रात का समय था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हल्की हवा बह रही थी। स्पिन बोलदाक और चमन की रेत के बीच फैली खामोशी अचानक गोलियों की आवाज से टूट गई। कुछ ही मिनटों में दोनों ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। सीमा के दोनों तरफ तैनात सैनिक अपनी-अपनी चौकियों से आग बरसाने लगे। आसमान में धुएं के बादल छा गए, गोलियों की चमक बिजली की तरह चमक रही थी। यह वही सीमा थी, जहाँ कभी दोनों देशों के व्यापारी हँसते हुए फल, सब्जियाँ और मसाले लेकर आया-जाया करते थे। आज वहाँ सन्नाटा और भय का साया फैल गया था। यह वही स्पिन बोलदाक-चमन क्रॉसिंग थी, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे व्यस्त सीमा बिंदुओं में से एक मानी जाती है। हजारों लोग रोज़ यहाँ से गुजरते थे—कोई इलाज के लिए, कोई काम के लिए, तो कोई अपने परिजनों से मिलने के लिए। लेकिन इस बार यह सीमा न केवल बंद थी, बल्कि मौत की छाया में डूबी हुई थी। अफगानिस्तान की ओर से दावा किए जा रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया है और सीमा की कई चौकियों पर नियंत्रण कर लिया है। जवाब में पाकिस्तान ने इसे "झूठ और भ्रम फैलाने वाला दावा" बताया, लेकिन सच यह था कि सीमा की दोनों ओर तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान की सीमा के भीतर मिसाइल दागी थी। यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर किया गया बताया गया था। मगर इस कार्रवाई ने तालिबान शासन को भड़काया। उन्होंने इसे "सार्वभौमिकता पर हमला" बताया और पलटवार की चेतावनी दी। शनिवार की रात वही चेतावनी हकीकत बन गई। अफगान बलों ने पाकिस्तान के सात सैनिकों को पकड़ लिया, और खबर आई कि उन्हें बंधक बना लिया गया था। रविवार की सुबह जब सूरज उगा, तो सीमा पर हर ओर सैन्य वाहनों की आवाजाही थी। अफगानिस्तान की ओर तालिबान के सशस्त्र दस्ते गश्त कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान की ओर से टैंक और तोपों की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में बारूद की गंध थी, और दोनों देशों की मीडिया एक-दूसरे पर दोषारोपण में लगी थीं। सीमा के आसपास बसे गाँवों में सन्नाटा पसर गया था। छोटे-छोटे कस्बे, जहाँ रोज़ हाट-बाज़ार लगते थे, अब वीरान थे। बच्चे अपने माता-पिता के साथ भूमिगत कमरों में छिपे थे। बाज़ारों के शटर गिरे हुए थे। जिन दुकानों में पहले अफगान सूखे मेवे और पाकिस्तानी मसाले बिकते थे, वहाँ अब सिर्फ धूल उड़ रही थी। सीमा पार के ट्रक महीनों की माल ढुलाई में अटके हुए थे।

संपादकीय

गाजा में स्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित हो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव व मध्यपूर्व के देशों की पहल के बाद गाजा में इस्राइल व हमास के बीच संघर्ष विराम की तसवीर उभरी है। यह कहना कठिन है कि यह समझौता कितने दिन टिकेगा क्योंकि समझौते के बाद भी इस्राइल ने गाजा के कुछ इलाकों में बमबारी की है। कहना मुश्किल है कि ट्रंप वास्तव में गाजा के लोगों को न्याय दिलाने चाहते हैं, या उनके समझौते के प्रयासों का लक्ष्य नोबेल शांति पुरस्कार पाना था। दरअसल, शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा और युद्धविराम की घोषणा की तिथियां आसपास ही थीं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिये ट्रंप जैसा उतावलापन दिखा रहे थे, उससे दुनिया की नंबर एक महाशक्ति के नायक की जगहंसाई ही हुई है। बहरहाल, गाजा में शांति स्थापना के प्रयासों का सिरे चढ़ना स्वागतयोग्य ही कहा जाएगा। हालांकि, इस समझौते के लिये ट्रंप द्वारा इस्राइल व हमास पर भारी दबाव डाला गया। दबाव में किया गया यह समझौता कितने दिन टिकेगा, कहना मुश्किल है। समझौते के बाद भी इस्राइल की बमबारी इस समझौते की दुखती रग है। वहीं हमास बीस सूत्री समझौते पर कितने दिन कायम रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। समझौते की शर्तों में हमास का निशस्त्रीकरण करना और गाजा में उसकी प्रशासनिक दखल बंद करना भी शामिल है। कहना कठिन है कि अरब देशों के दबाव में बातचीत की टेबल पर आया हमास इन शर्तों पर कब तक कायम रह पाता है। वह समझौते की टेबल पर तब आया जब ट्रंप ने समझौता न करने पर नेस्तनाबूद करने की धमकी दे दी थी। उल्लेखनीय है कि इस्राइल और हमास के बीच दो साल से जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने यह शांति योजना पेश की थी। जिसे मिस्र में आयोजित बातचीत में हितधारकों ने अंतिम रूप दिया। जिससे इस अशांत क्षेत्र और पश्चिमी एशिया में शांति की उम्मीद हकीकत बनी। दरअसल, इस संघर्ष से न केवल गाजा बल्कि लेबनान, यमन और ईरान तक को अपनी चपेट में ले लिया था।

दरअसल, यह संघर्ष दो साल पहले तब शुरू हुआ जब 7 अक्तूबर को हमास के आतंकवादियों ने इस्राइल में घुसकर कोहराम मचाया। उस हमले में बारह सौ इस्राइली व कुछ विदेशी मारे गए थे और ढाई सौ लोगों को बंधक बनाकर हमास के हमलावर गाजा ले गए थे। उसके जवाब में इस्राइल द्वारा किए गए ताबड़-तोड़ हमलों में करीब 65 हजार से अधिक फलस्तनियों के मारे जाने का दावा किया जाता है। आज गाजा भूतहा खंडहरों के शहर में तब्दील हो चुका है। लाखों लोगों को बार-बार पलायन के लिये मजबूर होना पड़ा है। विडंबना यह है कि भले ही इस्राइल ने हमास के क्रूर हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई की हो, मगर इन हमलों का शिकार आम फलस्तीनी नागरिकों को होना पड़ा है। मरने वालों में बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की है। यहां अस्पताल से लेकर तमाम सार्वजनिक सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की थी कि गाजा में लोग भुखमरी के शिकार हैं क्योंकि इस्राइल ने राहत सामग्री के पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इस्राइल और अमेरिका की देखरेख में शुरू किए गए कथित राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में इस्राइली हमलों में हजारों फलस्तीनी मारे गए थे। कालांतर, यह लड़ाई इस्राइल व लेबनान के बीच संघर्ष में तब्दील हुई। हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष के बाद लड़ाई ईरान तक पहुंची। हूतियों के हमलों से समुद्री मार्ग से होने वाला वैश्विक व्यापार तक बुरी तरह प्रभावित हुआ। बहरहाल, अब जब इस्राइल व हमास संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं तो अब प्रयास हो कि यह शांति स्थायी हो सके। हालांकि, मौजूदा हालात में यह कहना कठिन है कि बेहद आक्रामक तेवर दिखा रहा इस्राइल भविष्य में चुप बैठेगा। हमास बीस इस्राइली बंधकों तथा मारे गए लोगों के शव लौटाने को राजी हुआ है। जिसके बदले में इस्राइल द्वारा हमास के कुछ लड़ाकों समेत हजारों फलस्तीन कैदियों को रिहा किया जाना है। कहने को तो गाजा से इस्राइली सैनिकों की वापसी की शर्त भी है, लेकिन अमेरिकी सरपरस्ती में निरंकुश व्यवहार कर रहे इस्राइल से इस मुद्दे पर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है।

शांति दूत बनकर घूम रहे ट्रंप ने खुद ही छेड़ दिया युद्ध, US-China Trade War से दुनिया सकते में

> “ यह फैसला चीन के उस कदम के जवाब में आया है, जिसमें उसने दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Elements) के निर्यात पर नए नियंत्रण लगाए हैं। हम आपको बता दें कि यह खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में अनिवार्य हैं।

दूसरे युद्धों को खत्म कराने का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है और यह युद्ध बंदूकों का नहीं, बल्कि टैरिफ और दुर्लभ खनिजों का है। अमेरिका और चीन के बीच यह नया टैरिफ संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वैसा ही झटका है, जैसा 2018-19 के व्यापार युद्ध के समय देखा गया था। ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से चीन से आने वाले सभी सामानों पर 100% शुल्क लगाया जाएगा और “महत्त्वपूर्ण सॉफ्टवेयर” के निर्यात पर नई पाबंदियाँ लगेंगी। यह फैसला चीन के उस कदम के जवाब में आया है, जिसमें उसने दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Elements) के निर्यात पर नए नियंत्रण लगाए हैं। हम आपको बता दें कि यह खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में अनिवार्य हैं। बीजिंग दुनिया में इन खनिजों के 90% से अधिक परिशोधन (processing) पर नियंत्रण रखता है। ट्रंप ने चीन के इस कदम को “hostile order” यानी शत्रुतापूर्ण आदेश बताया और कहा कि बीजिंग “पूरी दुनिया को बंधक बनाने” की कोशिश कर रहा है।

इस नई आर्थिक जंग की घोषणा के साथ ही वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स 2.7% गिर गया, नैस्डैक में भी तेज़ गिरावट आई, जबकि निवेशक सोने की शरण में भागे। डॉलर कमजोर पड़ा और वैश्विक निवेशकों में यह आशंका फैल गई कि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच ‘टैरिफ युद्ध’ फिर से भड़क उठा है।

देखा जाये तो ट्रंप का यह फैसला केवल एक आर्थिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती है। चीन ने जब दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण बढ़ाया, तो उसने न केवल अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया की औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया। इन खनिजों के बिना स्मार्टफोन, मिसाइल, सेमीकंडक्टर और बैटरी बनाना असंभव है। इसलिए चीन का यह कदम भू-अर्थशास्त्र (geo-economics) की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह अपनी प्राकृतिक संपदाओं को राजनैतिक दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल करता है।

ट्रंप की प्रतिक्रिया उतनी ही आक्रामक है जितनी अप्रत्याशित। यह कदम न केवल बीजिंग के लिए बल्कि अमेरिका के उद्योगों के लिए भी दोहरी चुनौती बनेगा— क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ वर्षों से एक-दूसरे में गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ट्रंप की प्राथमिकता फिलहाल राजनीतिक लाभ और “मेड इन अमेरिका” की घरेलू भावना को पुनर्जीवित करना है।

उधर, चीन के लिए यह विकास चिंताजनक है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से धीमी वृद्धि, रियल एस्टेट संकट और घटती विदेशी मांग से जूझ रही है। ऐसे में अमेरिकी बाजार पर 100% टैरिफ उसके निर्यात क्षेत्र को गंभीर चोट पहुंचाएगा। चीन अब अपने प्रभाव को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि अमेरिकी दबाव को संतुलित किया जा सके। लेकिन ट्रंप के कदम का एक बड़ा असर यह होगा कि पश्चिमी कंपनियाँ चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। Apple, Tesla और अन्य अमेरिकी कंपनियाँ पहले ही ‘चाइना-प्लस-वन’ रणनीति पर काम कर रही हैं। अब यह प्रवृत्ति और तेज होगी।

दूसरी ओर, भारत के लिए यह परिदृश्य “संकट में अवसर” की तरह है। यदि दुनिया चीन पर निर्भरता घटाना चाहती है, तो भारत एक स्वाभाविक विकल्प बन सकता है। अमेरिका और यूरोप दोनों ही ऐसे साझेदार की तलाश में हैं जो भरोसेमंद हो, राजनीतिक रूप से स्थिर हो, और तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो। भारत के पास इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तीन प्रमुख रास्ते हैं। पहला- भारत में भी कई दुर्लभ खनिजों के भंडार हैं, परंतु उनका परिशोधन ढांचा कमजोर है। यदि सरकार इस क्षेत्र में ‘राष्ट्रीय रेयर अर्थ मिशन’ जैसे कार्यक्रम को गति दे, तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। दूसरा- ट्रंप की नीति से अमेरिकी कंपनियाँ चीन से हटकर भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया की ओर रुख करेंगी। भारत यदि भूमि सुधार, बिजली लागत और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाता है, तो यह निवेश आकर्षित कर सकता है। तीसरा- अमेरिका और जापान के साथ सेमीकंडक्टर और एआई अनुसंधान में सहयोग भारत को नई औद्योगिक शक्ति में बदल सकता है।

परंतु यह कहानी केवल अवसरों की नहीं है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध से वैश्विक मंदी की संभावना बढ़ सकती है। अमेरिका और चीन दोनों भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं; किसी भी झटके से भारतीय निर्यात, आईटी सेवा और ऑटो उद्योग प्रभावित होंगे। इसके अलावा, यदि चीन दुर्लभ खनिजों के निर्यात को भारत तक सीमित करता है, तो भारत की बैटरी, मोबाइल और रक्षा विनिर्माण योजनाएँ बाधित हो सकती हैं। इसलिए भारत को केवल अवसर नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन रणनीति भी तैयार करनी होगी।

देखा जाये तो अमेरिका-चीन टकराव वैश्विक शक्ति-संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। यह अब केवल व्यापार की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, संसाधन और प्रभाव क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बन चुका है। आने वाले वर्षों में यह संघर्ष तय करेगा कि दुनिया का औद्योगिक केंद्र एशिया में कहाँ स्थिर होगा— चीन में या उसके बाहर। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस नए वैश्विक भूगोल में ‘सप्लाई चेन रेजिलियंस’ का नेतृत्व करे। इसके लिए उसे खनिज नीति, औद्योगिक निवेश और तकनीकी अनुसंधान में साहसिक कदम उठाने होंगे।

कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप का यह ‘टैरिफ बम’ वैश्विक व्यापार में अस्थिरता का विस्फोट है। लेकिन इसके भीतर भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर छिपा है। यदि भारत इस चुनौती को दूरदृष्टि और नीति-संवेदनशीलता के साथ संभाले, तो वह न केवल इस तूफान से सुरक्षित निकल सकता है बल्कि इस नए वैश्विक आर्थिक युग में आत्मनिर्भर और निर्णायक शक्ति के रूप में उभर सकता है।

बहरहाल, ट्रंप ने भले ही दूसरे युद्धों को खत्म करने का दावा किया हो, परंतु उनका यह नया आर्थिक युद्ध आने वाले दशक का सबसे बड़ा वैश्विक शक्ति परीक्षण साबित हो सकता है— जिसमें भारत का प्रदर्शन यह तय करेगा कि वह केवल दर्शक रहेगा या इस नये आर्थिक युद्ध का विजेता।

सरोकार

लोकनायक की सादगी जिसने अपराधी का हृदय बदल दिया

साल 1975 का वह समय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक गहरी छाया की तरह दर्ज है। आपातकाल का दौर था। सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले हर व्यक्ति को जेलों में डाल दिया गया था। अख़बारों की स्याही पर पहरा था, और नागरिक स्वतंत्रता को जैसे जंजीरों में जकड़ दिया गया था। इन्हीं दिनों भारत के महान समाजवादी नेता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण—जो अन्याय के विरुद्ध आंदोलन के प्रतीक बन चुके थे—को भी जेल में कैद कर दिया गया।

एक दिन जेल के भीतर का साधारण-सा दृश्य इतिहास का अमर प्रसंग बन गया। सुबह का समय था, जब कैदियों को पानी पीने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था। जेल की गर्म और बंद हवा में सभी बेचैन थे। उसी कतार में एक दुबली, झुकी हुई काया, सफ़ेद खादी के वस्त्रों में सुसज्जित, शांत चेहरे वाला व्यक्ति अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे — जिनका नाम उस समय देश के हर कोने में आदर और सम्मान से लिया जाता था।

उनके ठीक बगल में एक और कैदी

खड़ा था — हाजी मस्तान। वही प्रसिद्ध तस्कर, जिसके पास धन, शक्ति और रौब का कोई अभाव नहीं था। जेल में आने के बाद भी उसका वीआईपी रुतबा बरकरार था। अधिकारी उसे “साहब” कहकर संबोधित करते, वह आदेश देता, दूसरों पर ऊँची नज़र से देखता और किसी भी असुविधा पर गुस्सा जताता। वह अपनी पहचान हर जगह बनाकर रखना चाहता था, चाहे वह जेल ही क्यों न हो।

लेकिन उस सुबह कुछ अलग हुआ। जब उसकी नजर जयप्रकाश नारायण पर पड़ी, तो वह ठिठक गया। एक बुजुर्ग नेता, जिनके लिए पूरी दुनिया आदर से झुकती थी, वे बिना किसी विशेषाधिकार के एक साधारण कैदी की तरह कतार में खड़े थे — शांत, संयमी, विनम्र। न कोई शिकायत, न कोई रौब, न कोई अधीरता। उनके चेहरे पर बस गहरी शांति थी, जैसे भीतर एक महासागर बह रहा हो।

हाजी मस्तान उस दृश्य को देखता रह गया। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा नेता भी इस तरह सामान्य जीवन जी सकता है। उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ नया जन्मा। अहंकार, शक्ति, दिखावा — सब अर्थहीन लगने लगा। उस दिन उसने पहली बार सादगी में छिपी महानता को देखा।

जेल में बिताए महीनों के दौरान हाजी मस्तान के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसने धीरे-धीरे अपने व्यवहार में संयम लाना शुरू किया। उसका रौब कम हो गया, और आत्मचिंतन बढ़ गया। करीब 18 महीने बाद जब वह जेल से रिहा हुआ, तो उसने सबके सामने घोषणा की कि वह अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ रहा है। उसने अपने साथी तस्करों — यूसुफ पटेल और सुकरनारायण बखिया — के साथ मिलकर ईमानदारी और सादगीपूर्ण जीवन जीने की शपथ ली।

देश के प्रमुख अख़बारों ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया। उन रिपोर्टों में तस्वीरें भी थीं — जिनमें हाजी मस्तान और अन्य कुख्यात तस्कर जयप्रकाश नारायण के सामने सिर झुकाकर प्रण कर रहे थे कि वे अब अपराध की राह छोड़ देंगे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस सादगी की विजय थी, जिसने किसी को डांटकर या दंड देकर नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता और चरित्रबल से बदल दिया।

जयप्रकाश नारायण ने किसी मंच से भाषण नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं किया। उन्होंने केवल अपने आचरण से दिखाया कि नैतिकता का असली स्वरूप दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में होता है। उनकी सादगी एक मौन क्रांति थी — जिसने अपराध की अंधेरी दुनिया में भी प्रकाश फैला दिया।

यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति हथियारों या पदों में नहीं होती। वह उस व्यक्ति में होती है, जो अपने व्यवहार से दूसरों को सुधार दे, जो बिना बोले सिखा दे कि सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जयप्रकाश नारायण की यह घटना इस बात का प्रतीक है कि एक सच्चे मनुष्य का जीवन ही सबसे बड़ा संदेश होता है। उनकी सादगी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सत्य और विनम्रता एक साथ खड़े होते हैं, तो झूठ और अपराध अपने आप झुक जाते हैं।

महिला-युवा तय करेंगे सरकार कौन बनाएगा

लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती—क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इतिहास दोहराएगी? मतदाताओं के रुख की हकीकत 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन लगता है कि एक बार फिर बिहार में महिला मतदाताओं का रुख ही बिहार की अगली सियासी तस्वीर का फैसला करने जा रहा है। वैसे इसमें युवाओं, विशेषकर पहली बार वोटर बने नौजवानों की भी अहम भूमिका रहने जा रही है।

बिहार के चुनाव में महिलाओं और युवाओं के महत्व का अंदाजा दोनों प्रमुख गठबंधनों को है। सत्ताधारी गठबंधन ने महिलाओं को लुभाने की जी-तोड़ कोशिश की है। राज्य में करीब साढ़े तीन करोड़ महिला वोटर हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिला मतदाताओं के करीब 22 फीसद को दस-दस हजार रुपये की रकम दी जा चुकी है। इस योजना के तहत राज्य की एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को इसका फायदा दिया जाना है। बेशक भाजपा विपक्ष शासित राज्यों में ऐसी ही सहयोग देने वाली योजनाओं को कभी ‘रेवड़ी’ बताकर विरोध करती रही हो, लेकिन अब वह भी ऐसी योजनाओं में भागीदारी कर रही है। छत्तीसगढ़ की जीत में महतारी वंदन योजना और मध्य प्रदेश की जीत में लाड़ली बहना योजना की भूमिका को शायद ही कोई दल नकार पाए। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब 10 जून, 2023 को जबलपुर में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी, तब माना जा रहा था कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में अलोकप्रिय हो चुकी है। लेकिन चुनावी नतीजों ने इस धारणा को बदल दिया। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया था कि भूपेश बघेल सरकार को हार का स्वाद चखना होगा, लेकिन ऐसा हुआ। माना गया कि सियासी तस्वीर बदलने में भाजपा की महतारी वंदन योजना का बड़ा हाथ रहा। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की जीत में भी अन्य कारकों के साथ लाड़ली बहना योजना और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की वापसी में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अहम भूमिका रही है।

पिछले कुछ चुनावों से महिलाओं ने मतदान में पुरुषों के पीछे चलने की अवधारणा को बदला है। वे बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जहां 59.69 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया था, वहीं पुरुषों का प्रतिशत महज 54.45 प्रतिशत ही था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर करीब 51 प्रतिशत ही है। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनावों से ही बिहार में महिलाएं केंद्र में हैं। तब जहां 51.12 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था, वहीं महिलाओं ने इससे कहीं ज्यादा यानी 54.49 प्रतिशत हिस्सेदारी की थी। इसी तरह 2015 के विधानसभा चुनाव में भी पुरुषों से आगे 60.48 फीसद महिलाओं ने वोट डाले थे। बिहार में इस बार करीब साढ़े तीन करोड़ महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.92 करोड़ है।

वास्तव में पलायन के चलते बिहार में पुरुष मतदाता कम हैं। मतदाता सूची में दर्ज नाम वाले भी वोटर परदेस में रोज़ी-रोटी कमाने को मजबूर हैं। इस बार भी बिहार की अगली सरकार के गठन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। महिलाओं की ही मांग पर नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी लागू की थी। आलोचनाओं के बावजूद अगर नीतीश इस योजना को जारी रखे हुए हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि उनका महिला वोटरों पर भरोसा तेजस्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। बिहार में इस बार 14 लाख ऐसे नए वोटर जुड़े हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। विधानसभावार आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हर विधानसभा में पहली बार वोट डालने वालों की संख्या औसतन 5,761 होती है। विधानसभा में जीत-हार का आंकड़ा बेहद नजदीकी होता है। जाहिर है कि इन नए मतदाताओं पर भी विधानसभा में जीत-हार निर्भर होगी। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव बार-बार युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी सरकार बनने की स्थिति में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का दावा भी कर रहे हैं। तेजस्वी खुद को युवा हितैषी साबित करने के लिए नीतीश कुमार के साथ रहते नौकरियों के बांटे गए दस्तावेजों का हवाला देने से भी नहीं चूक रहे। पलायन को विपक्षी खेमे की ओर से मुद्दा बनाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। बिहार में रोजगार की कमी के चलते यहां के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का रुख करने को मजबूर हैं। प्रशांत किशोर मतदान में युवाओं की ताकत को समझते हैं।

नजरिया

शिव-पार्वती द्वारा गणेश पूजन की दिव्य कथा

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उनके सम्मुख अनेक मुनि और देवता एकत्र होकर किसी महान यज्ञ के आयोजन की चर्चा कर रहे थे। यह एक दिव्य यज्ञ था, जिसमें देवताओं की सिद्धि, ऋषियों की तपस्या और ब्रह्मांड के कल्याण का संकल्प निहित था। मुनियों ने माता पार्वती और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे इस यज्ञ में सम्मिलित हों, क्योंकि उनके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता।

भगवान शिव और माता पार्वती ने मुनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने यज्ञ की विधि के अनुसार स्थान ग्रहण किया। जब यज्ञ का शुभ मुहूर्त आया, तो ऋषियों ने कहा — “देवदेव, किसी भी मंगल कार्य का प्रारंभ गणपति पूजन के बिना नहीं होता। अतः आप पहले गणेशजी का पूजन करें, तभी यह यज्ञ सफल होगा।”

शिवजी और पार्वतीजी यह सुनकर मुस्कराए। पार्वतीजी ने कहा — “मुनिवर, गणेश तो हमारे ही पुत्र हैं। क्या हमें अपने ही पुत्र की पूजा करनी चाहिए?” इस पर मुनियों ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा — “माता, यह संसार की विधि है। यद्यपि वे आपके पुत्र हैं, परंतु देवताओं में वे विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माने गए हैं। जो भी देव, दानव या मानव किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, उन्हें पहले गणेशजी की आराधना करनी होती है। अन्यथा कार्य अधूरा रह जाता है।”

मुनियों की यह बात सुनकर शिवजी गंभीर हो गए। उन्होंने पार्वतीजी की ओर देखा और बोले — “देवी, यह सत्य है। पुत्र होने पर भी गणेशजी आज समस्त सृष्टि के प्रथम पूज्य हैं। उनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।”

तब शिवजी और पार्वतीजी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने ही पुत्र गणेशजी का पूजन किया। उन्होंने उन्हें दूर्वा, मोदक, पुष्प और अक्षत अर्पित किए। शिवजी ने मंत्रोच्चार के साथ गणेशजी के समक्ष प्रणाम किया और कहा — “विघ्नेश्वर, तुम सृष्टि के आरंभ में स्थित प्रथम देवता हो। तुम्हारे नाम के बिना कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता। आज हम स्वयं तुम्हें पूजकर यह यज्ञ आरंभ कर रहे हैं।”

गणेशजी उस समय प्रसन्न होकर बोले — “पिताश्री, माताश्री! आपने स्वयं यह पूजन करके संपूर्ण जगत को यह संदेश दिया है कि देव, दानव, मानव — कोई भी हो — उसे अपने अहंकार का त्याग कर धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो भी मुझसे पहले पूजा करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं।”

जैसे ही गणेशजी ने यह वचन कहा, यज्ञ स्थल पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पुष्पों की वर्षा हुई और आकाश में देवगंधों की सुगंध भर गई। ऋषियों ने “जय गणेश, जय गणेश” का उच्चार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की।

उस दिन से यह परंपरा चली कि कोई भी देवता, ब्रह्मा, विष्णु या स्वयं महादेव भी, जब किसी शुभ कार्य का आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले गणेशजी का पूजन करते हैं। इसी कारण गणेशजी को “प्रथम पूज्य” और “विघ्नहर्ता” कहा जाता है।

यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब स्वयं महादेव और जगन्माता पार्वती भी अपने पुत्र गणेश की पूजा कर सकते हैं, तो मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता से आराधना करनी चाहिए। सच्ची भक्ति वहीं होती है जहाँ प्रेम, सम्मान और मर्यादा एक साथ हों। गणेशजी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि विनम्रता और मर्यादा के प्रतीक भी हैं — जो अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सबसे बड़ा वही नहीं जो शक्तिशाली है, बल्कि वही जो सबसे पहले “नमन” करना जानता है।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा, सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की फिर मुलाकात, बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण पर चर्चा

मुंबई। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात फिर चर्चा में आ गई है। रविवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपने चचेरे भाई और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे से मातोश्री में लगभग एक घंटे तक मिले। यह इस सप्ताह में दोनों की दूसरी मुलाकात थी, जिससे बीएमसी चुनाव के समीकरणों पर अटकलें तेज हो गई हैं।

राज ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह एक पारिवारिक मुलाकात थी। उन्होंने स्पष्ट किया, "मेरी मां मेरे साथ हैं और यह बैठक दो नेताओं की नहीं बल्कि दो भाइयों की थी।" हालांकि, मुंबई नगर निगम चुनाव के नजदीक होने के कारण इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि दोनों भाइयों के दल अलग-अलग लड़ते हैं तो यह उनके लिए नुकसानदेह होगा।

सूत्रों के अनुसार, बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के बीच गठबंधन पर बातचीत काफी हद तक पूरी हो चुकी है, और अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। दोनों दल अपने-अपने मतदाताओं और स्थानीय संगठन को मिलाकर चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं।

2024 के चुनाव में हार के बाद राज और उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक भविष्य और महाराष्ट्र में सत्ता समीकरण को देखते हुए एक-दूसरे के करीब आए हैं। दोनों दल आगामी निकाय चुनाव में मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे बीएमसी में सत्ता में आने की संभावनाओं को मजबूत किया जा सके। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे जल्द ही सार्वजनिक किए जाने की संभावना बता रहे हैं।

इस मुलाकात के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और राजनीतिक गलियारों में इस गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीएमसी चुनाव के दृष्टिकोण से यह मुलाकात महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल मतदाता समीकरण प्रभावित होंगे, बल्कि चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर भी असर पड़ सकता है।

संक्षिप्त समाचार

ज़िला परिषद व पंचायत समिति चुनावों की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, आपत्तियों के लिए 13 और 14 अक्टूबर अंतिम तिथि

भिवंडीः ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जारी की गई प्रारूप मतदाता सूचियों पर आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए अब केवल दो दिन 13-14 अक्टूबर का समय शेष है।

भिवंडी तहसीलदार अभिजीत खोले ने जानकारी दी कि जो नागरिक या राजनीतिक दल इन सूचियों पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे निर्धारित समयावधि में तहसीलदार कार्यालय में अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। भिवंडी तालुका के 21 ज़िला परिषद गट और 42 पंचायत समिति गण के लिए प्रारूप मतदाता सूचियाँ 8 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थीं। नागरिकों और दलों की सुविधा के लिए ये सूचियाँ तहसीलदार कार्यालय स्थित निवासी नायब तहसीलदार के कक्ष में अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई गई हैं।

अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के घर पहुँचकर पुलिस ने बाँटी मिठाइयाँ और स्नेह

ठाणे। दिवाली खुशियों, रोशनी और अपनत्व का पर्व है, परंतु महानगरों की व्यस्त ज़िंदगी में कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो यह त्योहार अकेले मनाते हैं। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, रिश्तेदार दूर हैं, और दरवाज़ा खटखटाने वाला कोई नहीं होता। ऐसे अकेलेपन में, कोपरी पुलिस ने मिठाइयों, फूलों और स्नेह के साथ उनके जीवन में रोशनी भर दी।

ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे के मार्गदर्शन में कोपरी पुलिस ने 'वरिष्ठ नागरिक सेवा अभियान' के तहत यह पहल की। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस अधिकारी उन बुज़ुर्गों के घर पहुँचकर उनकी ज़रूरतों का हाल-चाल पूछते हैं और दिवाली के अवसर पर मिठाइयाँ बाँटकर उन्हें खुशियों का एहसास कराते हैं।

हर वर्ष की तरह इस बार भी कोपरी पुलिस ने यह परंपरा निभाई। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने बुज़ुर्गों को मिठाई और शुभकामनाएँ दीं। कई वरिष्ठ नागरिकों की आँखें भावुक होकर छलक पड़ीं — "पुलिस ने हमें अपनापन महसूस कराया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निशिकांत विश्वकर, पुलिस उपनिरीक्षक सीताराम गावित, जितेंद्र खलाटे और बापू कोलेकर उपस्थित थे। वरिष्ठ निरीक्षक निशिकांत विश्वकर ने बताया कि हमने अपने इलाके के सभी अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों का व्यक्तिगत विवरण दर्ज किया है। अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होती है, तो पुलिस तुरंत पहुँचती है। हमारा उद्देश्य है — वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित, संतुष्ट और खुश रहें!

पुणे में अवैध सेक्स रैकेट का खुलासा, दो बांग्लादेशी महिलाएं बचाई गईं

पुणे। पुणे शहर पुलिस ने दो बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध सेक्स रैकेट से बचाया, जिसमें महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर भारत लाया गया और बाद में उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। पहले 22 साल की महिला को कटराज क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दो साल पहले उसे वेस्ट बंगाल से अवैध तरीके से भारत लाया गया था और पुणे में नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन यहां उसे सेक्स रैकेट में फंसा दिया गया। पहली महिला की शिकायत के बाद भारती विद्यापीठ पुलिस ने वरिष्ठ इंस्पेक्टर राहुलकुमार खिलारे और सहायक इंस्पेक्टर स्वप्निल पाटिल के मार्गदर्शन में अभियान शुरू किया। जांच में पता चला कि एक और 20 साल की बांग्लादेशी महिला इसी तरह फंसी हुई थी। पुलिस ने अंबेगांव पथर के एक अपार्टमेंट पर छापा मारकर उसे भी सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने तस्करी में शामिल एक व्यक्ति, राजू पाटिल, निवासी ढांकवाड़ी को गिरफ्तार किया। उनकी पत्नी, जो कथित रूप से सहयोगी मानी जा रही है, अभी फरार है। भारती विद्यापीठ थाना में संबंधित धाराओं और 'Prevention of Immoral Trafficking Act' के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब उस नेटवर्क की जांच कर रही है, जिसने महिलाओं को अवैध तरीके से भारत लाने और रैकेटियों के हवाले करने में मदद की।

वरिष्ठ इंस्पेक्टर राहुलकुमार खिलारे ने कहा कि इन दोनों महिलाओं को सैलून में नौकरी का झांसा देकर फंसाया गया और फिर उन्हें सेक्स रैकेट में धकेला गया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने यह सफलता सिर्फ 24 घंटे में हासिल की। उन्होंने यह भी कहा कि महिला तस्करी और अवैध सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस सतर्क है और समय रहते कार्रवाई कर पीड़ितों को बचा रही है। इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया कि पुलिस इस तरह के अपराधों के खिलाफ कड़ी निगरानी रख रही है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ की ऐतिहासिक उपलब्धि: 'बेस्ट संस्था' का सर्वोच्च लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवॉर्ड का मिला सम्मान

मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुए संजय शाह, अल्पाबेन शाह तथा अशोक चारला

मुंबईः धर्म और संस्कार के प्रचार–प्रसार में अग्रणी श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। संस्था को यूके के अति प्रतिष्ठित सम्मान 'लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान संस्था की टीम को उक्त संस्था के भारत में प्रतिनिधि डॉ अविनाश साकुंडे के हाथों प्रदान किया गया। इसके साथ ही संघ के अग्रणी पदाधिकारियों को जैन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का प्रसार और पाठशालाओं की अमूल्य भूमिका के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होने वालों में श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ के उपाध्यक्ष संजय जीवनलाल शाह, ट्रस्टी अशोक नरसी चरला तथा महिला विभाग की उपाध्यक्ष अल्पाबेन संजय शाह का समावेश है। गौरतलब हो कि श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ ने धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर संस्था और पदाधिकारियों ने एक ऐतिहासिक स्थान प्राप्त किया है। संघ द्वारा देश भर में 655 जैन पाठशालाओं का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें 75,000 से अधिक बच्चे जैन धर्म और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।

हर वर्ष 25,000 से अधिक विद्यार्थी धार्मिक परीक्षा देते हैं, ये उपलब्धियां समाज में बढ़ते धार्मिक आकर्षण और संघ की सशक्त कार्यशैली का प्रमाण हैं। यह सम्मान संस्था की दशकों पुरानी सेवा और भविष्य में धार्मिक शिक्षा का विस्तार और राष्ट्रीय उपलब्धि और धर्म प्रचार के संकल्प को और मजबूत बनाएगी।

साथ ही यह संस्था के धार्मिक शिक्षा के बढ़ते योगदान को दर्शाती है। इस अवसर पर श्री नेमिसूरी समुदाय के आचार्य भगवंत प.पू. श्री चंद्रसूरीश्वरजी महाराज तथा साधु-साध्वियों ने निश्रा प्रदान की, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। पूज्य श्री ने श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ को 'बेस्ट संस्था' का सर्वोच्च अवॉर्ड तथा अग्रणी पदाधिकारियों को

मानद डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करने पर अपना आशीर्वाद दिया और पूज्य श्री ने कहा कि यह बच्चों के ज्ञान का सम्मान है। प्रवचन में पूज्य श्री ने कहा कि जैन शासन में पहला कदम पाठशाला है। यही पाठशाला बच्चों में संस्कारों का सिंचन करती है। श्री जैन धार्मिक शिक्षा संघ के उपाध्यक्ष संजयभाई जीवनलाल शाह ने कहा कि यदि जैन शिक्षा को पांच वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक धार्मिक शिक्षा की नई तकनीक के माध्यम से संस्कृत भाषा प्रदान

की जाए तो बच्चों का विकास अवश्य होगा। धार्मिक शिक्षा की इस नई तकनीक से भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के देशों में रहने वाले जैन बच्चों को भी लाभ मिलेगा। जैन धर्म विश्व का एक प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म है, जो जीवदया, अहिंसा और आत्मशुद्धि पर जोर देता है। पाठशाला इस धर्म के मूल रूप के सिद्धांतों को बच्चों में रोपने का पवित्र कार्य करती है। उन्होंने कहा कि पाठशाला के माध्यम से बच्चों को धार्मिक ज्ञान के साथ संस्कार, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षा दी जाती है। यह भविष्य की पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़े रखने का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है, जो उन्हें विनय, विवेक और जीवदया जैसे गुण सिखाकर, आत्मा और संस्कृति के महत्व को समझाता है। ट्रस्टी अशोक नरसिंह चरला ने कहा कि मुंबई के 655 से अधिक स्कूलों में 1400 से अधिक शिक्षक और शिक्षिका अपना योगदान दे रहे हैं। आज मुंबई के स्कूलों में 75,000 से अधिक बच्चे धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। महिला विभाग की उपाध्यक्ष अल्पाबेन शाह ने कहा कि, आज के बच्चे ही आने वाले कल में जैन धर्म के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाएंगे। श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ की यह उपलब्धि केवल एक अवॉर्ड नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी में संस्कार और जैन धर्म के ज्ञान के बीज बोने वाली एक प्रेरणादायक यात्रा है। बता दें कि श्री संघ द्वारा 3 से 11 वर्ष के छोटे बच्चों के ज्ञान और तप के पुरुषार्थ को सम्मानित करने के लिए बाबूलनाथ स्थित श्री सहस्त्र फणा श्वेतांबर मूर्तिपूजक तपागच्छ संघ में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में धर्म का गहरा ज्ञान प्राप्त करने वाले 150 बच्चों को विशेष पुरस्कार और इनाम देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस अवसर पर मुंबई महानगरपालिका के पूर्व उपमहापौर बाबूभाई भवानजी, इंटरनेशनल ह्यूमन राईट्स अंबेसडर आर्गनाइजेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ अविनाश साकुंडे,

राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अफसर चांद कुरैशी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ यतिन देवधर, महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष राजेश उपाध्याय, महिला विभाग की प्रदेश उपाध्यक्ष मंदा ताई शिंदे, अखिल भारतीय पत्रकार हक सांसद समिति के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रमेश आयरे, समाजसेविका बिमल साटम, प्रदीप चौकशी, विक्रम शाह, धीरेंद्र जवेरी, राजेश दोशी, शिरीन जरीवाला, शांति भाई संघवी समेत जैन समाज के अनेक गणमान्य, कई जैन संस्थाओं के ट्रस्टीगण, संघ के सदस्य, धर्म-प्रेमी उपस्थित रहे, जिनका सम्मान श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ की ओर से किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ कमलेश गगलानी ने तथा आभार संजय शाह ने व्यक्त किया।

आदर्श डिलीशियस स्वीट्स में ग्राहकों की पहली पसंद बनी पारंपरिक मिठाइयाँ

कल्याणः दिवाली पर्व पर मिठाइयों की दुकानों में रौनक बढ़ गई है। आदर्श डिलीशियस स्वीट्स के संचालक नरेश चौधरी ने बताया कि इस बार ग्राहकों के बीच पारंपरिक गुलकंद बर्फी की सबसे अधिक मांग देखी जा रही है।

यह बर्फी दूध, चीनी और गुलकंद से तैयार की जाती है। इसका हल्का मीठा स्वाद और गुलाब की मनमोहक खुशबू ग्राहकों को विशेष रूप से पसंद आ रही है। इसके अलावा पनीर जलेबी, मटर कचौरी, चीज़ समोसा और मूंग की कचौरी जैसी नमकीन वस्तुएँ भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। वहीं बंगाली मिठाइयों में मलाई सैंडविच, चमचम और रस मलाई लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं।

दुकान पर विभिन्न प्रकार की बर्फियों के साथ करीब आठ तरह के पेड़े भी उपलब्ध हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर इन मिठाइयों की सुगंध और स्वाद लोगों के त्योहार में अतिरिक्त मिठास घोल रहे हैं।

पूर्व स्टेशन अधीक्षक रामचंद्र मिश्रा का निधन, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी में हुआ अंतिम संस्कार

जौनपुर। गोनापार गांव निवासी एवं पूर्व स्टेशन अधीक्षक रामचंद्र मिश्रा का मंगलवार को हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही गांव तथा आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। श्री मिश्रा ने लंबे समय तक मुंबई रेलवे में स्टेशन अधीक्षक के रूप में कार्य किया। वे अपनी ईमानदारी, कर्मनिष्ठा और सौम्य स्वभाव के कारण सहकर्मियों और समाज में अत्यंत सम्मानित थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे अपने पैतृक गांव गोनापार (जौनपुर) में रहकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। परिजनों में उनके तीन पुत्र — टीटीई पंकज मिश्रा, विजय मिश्रा और अजय मिश्रा हैं। भाइयों में सभनारायण मिश्रा और डॉ. प्रेमचंद्र मिश्रा शामिल हैं, जबकि भतीजों में सूरज मिश्रा एवं आशुतोष मिश्रा हैं। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी के मनकर्णिका घाट पर किया गया, जहाँ परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। रामचंद्र मिश्रा अपने स्नेहिल स्वभाव, सेवाभावी जीवन और सरल व्यक्तित्व के लिए समाज में सदैव स्मरण किए जाएंगे।

राहनाळ ग्रामपंचायत में प्रभारी सरपंच प्रताप पाटील की पहल पर करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित

भिवंडीः दसवीं और बारहवीं के बाद कौन-सी शैक्षणिक दिशा चुनी जाए, इस दुविधा को दूर करने के लिए भिवंडी तालुका की राहनाळ ग्रामपंचायत में प्रभारी सरपंच प्रताप पाटील की पहल पर रविवार को करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन जन केसरी संस्था के सहयोग से ग्रामपंचायत सभागृह में किया गया, जिसमें प्रो. हर्षद सुनील पाटील और प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ मंथन सुनील पाटील ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर विकल्पों की जानकारी दी। प्रताप पाटील ने विद्यार्थियों को जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, माता-पिता का विश्वास जीतने और निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में ग्राम समिति अध्यक्ष राजेंद्र भोईर, ग्रामपंचायत सदस्य एवं ग्रामस्थ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उपस्थित जनों ने प्रताप पाटील की इस पहल की सराहना की।

मनोज रानाडे ने ठाणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला

ठाणेः जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे (बी.ए.एस.) का स्थानांतरण जलगाँव के जिला कलेक्टर पद पर किया गया है। उनके पद का अतिरिक्त कार्यभार पालघर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानाडे (बी.ए.एस.) को सौंपा गया है।

रोहन घुगे को 8 अक्टूबर 2025 की दोपहर को ठाणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से मुक्त किया गया, जिसके बाद मनोज रानाडे ने 10 अक्टूबर 2025 को दोपहर में इस पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

रोहन घुगे के नेतृत्व में ठाणे जिला परिषद ने विकास के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं। कार्यभार ग्रहण करते हुए मनोज रानाडे ने कहा कि "हम इस विकास यात्रा को और अधिक गति देंगे तथा नागरिक-उन्मुख, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखेंगे।"

नालासोपारा में "मनोत्सव 2025" का शुभारंभ

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता हेतु विविध गतिविधियाँ, 10 व्यक्तियों को मिला "मनोविर पुरस्कार"

राष्ट्रीय स्वाभिमान। प्रेम चौबे

विरारः विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वसई-विरार व्यवहारिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान संस्थान तथा विभास मनोविकार अस्पताल द्वारा आयोजित सप्ताहव्यापी उत्सव "मनोत्सव 2025" का शुभारंभ नालासोपारा में हुआ। यह आयोजन 10 से 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक बीमारियों से जुड़े कलंक को दूर करना है। इसके तहत विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में विविध जनजागरण गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. सुरेश पाटिल ने "तनाव प्रबंधन" विषय पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया, जबकि डॉ. कीर्ति टंडेल ने मनोचिकित्सा से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने पर अपने विचार व्यक्त किए।

मानसिक स्वास्थ्य के संदेश को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए ऋद्धिविनायक नर्सिंग कॉलेज, उदय गिर नर्सिंग कॉलेज और भक्तिवेदांत अस्पताल (मीरा रोड) के विद्यार्थियों ने नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संवेदनशील प्रस्तुतियाँ दीं।

इस अवसर पर पालघर जिले में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 10 व्यक्तियों को "मनोविर पुरस्कार 2025" से सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि "मनोत्सव 2025" के माध्यम से समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और लोगों में संवाद, संवेदना व सहयोग की नई ऊर्जा का संचार होगा।

भिवंडी-ठाणे बायपास रोड पर कंटेनर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, तीन घंटे यातायात ठप

भिवंडीः मुंबई-नाशिक महामार्ग पर, जो हमेशा ट्रैफिक जाम से जूझता रहता है, ठाणे-भिवंडी बायपास रोड पर रविवार को कम यातायात के बावजूद सुबह करीब 11 बजे ठाणे की ओर जा रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। यह कंटेनर फिसलकर ओवाली खिंड स्थित आरडी ढाबा के पास बन रहे फ्लाईओवर के पास सड़क के बीच में आड़ा होकर गिर गया, जिससे ठाणे की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया।

इस दुर्घटना से सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं बची थी। घटना की जानकारी मिलते ही नारपोली ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार इस तरह का हादसा देखा है। काफी

मशक्कत के बाद, चार हाइड्रा क्रेन मंगवाकर लगभग तीन घंटे में कंटेनर को सीधा किया गया और चालकों ने बड़े प्रयास से उसे हटाया। नारपोली ट्रैफिक शाखा के पुलिस उपनिरीक्षक दीपक शेणवी ने बताया कि इस दुर्घटना में कंटेनर चालक घायल हुआ है, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

हालांकि, इस दुर्घटना के कारण मुंबई-ठाणे की ओर जाने वाला यातायात तीन घंटे तक ठप रहा, जिससे इस मार्ग पर पांच किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई वाहन चालकों ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए विपरीत दिशा की लेन से वाहन आगे बढ़ाए, जिससे ठाणे से भिवंडी की ओर जाने वाले रास्ते पर भी भारी जाम लग गया। ट्रैफिक विभाग की नारपोली और कोनगांव शाखा के पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अब यातायात को सामान्य करना शुरू कर दिया है।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail.com

भाजपा ने सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर कर सरकार की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है : कांग्रेस

मुंबई। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने रविवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को सुनियोजित तरीके से कमजोर और प्रभावहीन बना दिया है। उन्होंने बताया कि आरटीआई की शुरुआत में यह कानून नागरिकों को सशक्त बनाने और भ्रष्टाचार उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन अब यह अपने मूल उद्देश्य से दूर होता जा रहा है। सपकाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने आरटीआई को केवल औपचारिकता तक सीमित कर दिया है और वास्तविक जनसशक्तिकरण पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है।

सपकाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सूचना आयुक्तों के पद लंबे समय से खाली रखे जा रहे हैं, जिससे कानून का प्रभाव कम हो गया है। इसके अलावा, गोपनीयता के नाम पर सार्वजनिक डेटा साझा करने से लगातार इनकार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक और निर्वाचन आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे आम जनता के लिए आवश्यक जानकारी हासिल करना मुश्किल हो गया है। सपकाल ने विशेष रूप से नोटबंदी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियों, जैसे मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज, जनता से छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।

कांग्रेस ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आरटीआई अधिनियम को मजबूत करने और नागरिकों के सूचना अधिकार को बहाल करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान में कानूनी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें आरटीआई का सही उपयोग करने के तरीके सिखाए जा सकें। इसके साथ ही आम लोगों की प्रतिक्रियाओं और अनुभवों को एकत्रित कर सरकार पर दबाव बनाने की भी योजना है। सपकाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि वे समाज में जाति-आधारित विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस समाज में ब्रिटिश काल की 'फूट डालो और राज करो' रणनीति को अपनाकर राजनीतिक फायदे बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। सपकाल ने कहा कि उनकी राजनीतिक सोच नाथूराम गोडसे की मानसिकता की याद दिलाती है, और इससे समाज में कट्टरता और असमानता बढ़ रही है।

सपकाल ने हाल ही में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय घटक दलों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाएंगे और किसी एक पार्टी के मनमाने निर्णय गठबंधन की रणनीति को प्रभावित नहीं करेंगे। उनका कहना था कि विपक्षी दल मिलकर ही लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और जनता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेंगे।

सपकाल के इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस आरटीआई अधिनियम को मजबूत करने और नागरिकों के सूचना अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने जा रही है। इसके साथ ही राजनीतिक आलोचना के माध्यम से वह सरकार की नीतियों और पारदर्शिता की कमी को उजागर कर रही है, ताकि आम जनता में जागरूकता और लोकतांत्रिक सक्रियता बढ़ सके।

महाविकास आघाड़ी में चुनाव आयोग बैठक को लेकर मतभेद, आज तय होगा प्रतिनिधिमंडल

मुंबई। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी के विपक्षी दलों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल तैयार किया जाना है, लेकिन इसमें किन नेताओं को शामिल किया जाएगा, इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। विपक्ष में मतभेद का मुख्य कारण मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर असमंजस है। बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की सूची सोमवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल यह सुनिश्चित है कि शिवसेना (ठाकरे गुट) और मनसे के नेता बैठक में भाग लेंगे। चुनाव आयोग से मिलने का नेतृत्व एमएलसी अनिल परब करेंगे। बैठक में शामिल होने की घोषणा ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने की। उनके अनुसार एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और मनसे प्रमुख राज ठाकरे बैठक में मौजूद रहेंगे।

सत्ता पक्ष की ओर से इस बैठक में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि सोमवार को होने वाली बैठक में ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि प्रतिनिधिमंडल में किस पार्टी के कौन नेता शामिल होंगे।

पुणे में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लीलता का मामला, शिक्षक गिरफ्तार

पुणे जिले के स्वारगेट इलाके से एक चिंताजनक और शर्मनाक खबर सामने आई है। स्थानीय पुलिस ने एक 46 वर्षीय शिक्षक सुरेश दौलत रौंदल को नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी स्वारगेट के गौरव राज बिल्डिंग, दत्तनगर, अंबेगांव, कात्रज का निवासी है और इलाके में निजी ट्यूशन क्लास चला रहा था।

घटना के विवरण के अनुसार, यह मामला 9 अक्टूबर, गुरुवार सुबह लगभग 7:45 बजे का है। उस समय छात्रा क्लास में अकेली थी। पुलिस ने बताया कि रौंदल ने कथित तौर पर छात्रा से अश्लील बातें कीं और उसे यह कहकर प्रभावित करने की कोशिश की कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उसे अपने स्कूल में नौकरी दिलाएगा और एक सोने की अंगूठी भी देगा।

छात्रा की सूझबूझ और परिजनों की तत्परता ने मामले को गंभीरता से उठाने में अहम भूमिका निभाई। छात्रा ने तुरंत अपने परिवार को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने स्वारगेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया।

कानूनी प्रक्रिया के तहत, रौंदल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। स्वारगेट पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि कहीं कोई और पीड़ित तो नहीं है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जांच पूरी होने तक मामले का हर पहलू खंगाला जाएगा।

स्थानीय समाज में इस घटना ने गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और किसी भी असामाजिक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील कर रहे हैं। यह मामला एक बार फिर यह स्पष्ट करता है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित वातावरण के लिए परिवार, शिक्षक और प्रशासन को सतत जागरूक रहना बेहद आवश्यक है।

मामले की आगे की जांच चल रही है और पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि आरोपी को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

आरटीआई कानून मजबूत किया जाए, किसानों की सोयाबीन हमीभाव पर खरीदी होः हर्षवर्धन सपकाल

मुंबईः महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जानकारी के अधिकार (आरटीआई) कानून को कमजोर कर जनता के हक को बाधित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस आरटीआई को सशक्त बनाने के लिए लगातार आवाज उठाएगी।

सपकाळ ने भाजपा पर "भारत का तालिबान" बनाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में महिला पत्रकारों को पत्रकार परिषद में प्रवेश न देने की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा सरकारी तंत्र और सूचना पर

नियंत्रण से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।

उन्होंने राज्य में शांति भंग करने और जातीय तनाव फैलाने के प्रयासों की भी आलोचना की।

साथ ही हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि सोयाबीन का हमीभाव 5,400 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों से केवल 3,200–3,700 रुपये में खरीदी की जा रही है, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि हमीभाव पर खरीदी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा राज्य में एक भी मंत्री को बिना जवाबदेही के घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सपकाळ ने कहा कि कांग्रेस किसान, लोकतंत्र और महिला पत्रकारिता के संरक्षण के लिए हमेशा सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी।

तुर्भे में पुराने विवाद के बहाने हमला, 23 वर्षीय युवक की एमजीएम अस्पताल में मौत

नवी मुंबईः तुर्भे सेक्टर-21 में पुराने विवाद को सुलझाने के बहाने बुलाकर 23 वर्षीय किशोर वरक पर जानलेवा हमला किया गया। हमला 8 अक्टूबर 2025 की रात करीब साढ़े बारह बजे हुआ। आरोपियों ने क्रिकेट बैट, फाइबर रॉड, पत्थर और सीमेंट की ईंटों से हमला किया। इस हमले में किशोर वरक गंभीर रूप से घायल हुआ और एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

इस घटना में आशुतोष धुर्वे और विकी कांबळे भी घायल हुए। एपीएमसी पुलिस स्टेशन में विकी पाटिल, संकेत लाड उर्फ लाडु,

ओंकार वाघमारे, विघ्नेश घरत, शकील, मौला, चारुशिला और तीन अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ IPC और BNS की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। युवक की मौत की खबर मिलते ही एमजीएम अस्पताल और तुर्भे इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया। परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना रहा।

मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 10.4 किलो सोना जब्त, 13 गिरफ्तार

मुंबई। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 'ऑपरेशन गोल्डन स्वीप' के तहत मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो 448 ग्राम सोना जब्त किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सोने की कीमत लगभग 12 करोड़ 58 लाख रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आठ विदेशी और पांच भारतीय शामिल हैं। डीआरआई अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में छह श्रीलंकाई, दो बांग्लादेशी, दो हवाई अड्डे के कर्मचारी, दो हैंडलर और मुख्य आरोपी शामिल हैं।

श्रेयस मीडिया पूरे भारत में कार्निवल आयोजित करने के लिए तैयार

मुंबईः श्रेयस मीडिया द्वारा आयोजित विजयवाड़ा उत्सव ने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान पाकर दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल बनकर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। कंपनी ने अब देशभर में बिहू, ओणम, गणेश चतुर्थी, पोंगल, लोहड़ी, दुर्गा पूजा और संक्रांति जैसे त्योहारों पर बड़े कार्निवल आयोजित करने की योजना बनाई है।

श्रेयस मीडिया आंध्र प्रदेश के अराकू और गंडिकोटा जैसे पर्यटन स्थलों पर विदेशी कलाकारों के साथ सालभर उत्सव मनाएगी। कृषि को बढ़ावा देने के लिए संक्रांति पर भव्य किसान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विजयवाड़ा उत्सव की तर्ज पर विशाखापत्तनम और तिरुपति में नववर्ष और संक्रांति मनाए जाएंगे, वहीं विजयवाड़ा में दिवाली, नववर्ष और संक्रांति उत्सव होंगे। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में सालभर 30 बड़े संगीत कार्यक्रम और अराकू कॉफ़ी महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा।

श्रेयस मीडिया के संस्थापक गंद्रा श्रीनिवास राव ने बताया कि

विजयवाड़ा उत्सव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आयोजित कर कंपनी ने कार्निवल क्षेत्र में अपनी बौद्धिक संपत्ति स्थापित की है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा, रोजगार सृजित करेगा और देश-विदेश के लोगों को जोड़ने का अवसर देगा।

इस साल विजयवाड़ा उत्सव में करीब 50 लाख लोगों ने भाग लिया, जिससे स्थानीय स्तर पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ और 25,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। श्रीनिवास ने बताया कि अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है, और राज्य सरकारों के सहयोग से यह योजना पूरे भारत में लागू की जाएगी।

एसके हेयरड्रेसिंग स्कूल ने मुंबई में खोला नया प्रशिक्षण केंद्र

मुंबईः भारत में हेयरड्रेसिंग के क्षेत्र में विश्वस्तरीय शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध एसके हेयरड्रेसिंग स्कूल ने आज मुंबई में अपना दूसरा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। यह केंद्र महालक्ष्मी स्थित टंटिया जोगानी एस्टेट में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य भारतीय सैलून उद्योग में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करना तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना है। गुरुग्राम में इस साल की शुरुआत में खोले गए पहले सैलून के बाद, मुंबई का नया केंद्र वर्तमान और नए हेयरड्रेसर्स दोनों को उन्नत तकनीकी और व्यवसायिक कौशल प्रदान करेगा। एसके ब्यूटी रिसोर्सेज के निदेशक शुभम विरमानी ने कहा कि यह स्कूल सभी स्तर के पेशेवरों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। उनके अनुसार, यह पहल नए विद्यार्थियों और अनुभवी हेयरड्रेसर्स को श्रेष्ठ और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराएगी। दूसरे निदेशक अंकित विरमानी ने बताया कि आधुनिक प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म के माध्यम से सैलून पेशेवरों को नई तकनीकों, ज्ञान और उद्योग के नवीनतम रुझानों से लैस किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह कदम देश के ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर में कौशल और मानकों को ऊँचा उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। एसके हेयरड्रेसिंग स्कूल का यह विस्तार संगठित सैलून सेक्टर में प्रशिक्षित स्टाइलिस्टों की कमी और सैलून मालिकों की भर्ती संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

मुंबई में मानसून के बाद बिगड़ी वायु गुणवत्ता, तापमान में तेजी

मुंबई। इस साल मई में मानसून की हलचल के बाद अब मुंबई और उपनगरों में मानसून की वापसी के साथ अक्टूबर की हीट ने दस्तक दी है। इसके असर से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बिगड़ने लगा है और मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि दिवाली के बाद पर्यावरणीय संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मुंबई शहर और उपनगरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लोग तपिश भरी गर्मी से परेशान हैं और आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के डैशबोर्ड के अनुसार रविवार सुबह मुंबई का एक्यूआई 156 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है, जबकि देवनार क्षेत्र में यह 288 पहुंच गया, जो 'खराब' श्रेणी में है।

मुंबई शहर के 24 एक्यूआई निगरानी केंद्रों में से 21 में 'मध्यम', दो में 'संतोषजनक' और एक स्थान पर 'खराब' एक्यूआई दर्ज किया गया। मानसून की विदाई के बाद से ही वायु गुणवत्ता लगातार गिर रही है। अक्टूबर की शुरुआत में 1 से 9 तारीख तक एक्यूआई 100 से नीचे था, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता था। 10 अक्टूबर को यह बढ़कर 134 और अगले दिन 152 हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह और खराब हो सकता है। राष्ट्रीय उन्नत विज्ञान संस्थान (एनआईएएस) के चेयर प्रोफेसर डॉ. गुफरान बेग ने बताया कि मानसून के तुरंत बाद शहर का एक्यूआई बिगड़ना शुरू हो गया। साल 2021 की सर्दियों में भी ऐसा देखा गया था जब पश्चिमी तट पर हवाएं धीमी हो गई थीं। इस साल अक्टूबर के अंत तक हवा की दिशा और गति में कमी आने की संभावना है, जिससे नवंबर में मुंबई की वायु गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है। विशेषज्ञों ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अधिक धूल, प्रदूषित हवा और धुएं से बचें और घर में हवा शुद्ध रखने के उपाय करें। बढ़ती गर्मी और प्रदूषण का संयोजन शहरवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है।